(iii) Early Construction of Sutlej-Yamuna link canal in Punjab.

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, पंजाब व हरियाणा में पानी के बंटवारे के बाद जो पानी हरियाणा को मिलना चाहिए था, जो पानी मिल रहा है, उसको पूरे पानी के रूप में हरियाणा उपयोग करे, इसके लिए एस० वाई० एल० (सतलुज यमुना लिंक) नाम का एक चन्द किलोमीटर का टुकड़ा, जो पंजाब की जमीन में से होकर आता है, बनाने का आपसी फैसला सन् 1981 के शुरू में हरियाणा व पंजाब दोनों राज्यों ने आपस में भारत सरकार की मध्यस्थता में तय किया और समयबद्ध डेढ़ साल में यह लिंक नहर बनकर तैयार होने का वादा किया जो कि सन् 82 के अन्त तक हो जाना चाहिए था। उसका खर्चा हरियाणा सरकार को आधा देना करार पाया। हरियाणा सरकार ने साढ़े बीस करोड़ रुपया पंजाब सरकार को दे दिया। जो पैसा इंजीनियर और सरकारी नौकरशाह, जो उस खुदाई के लिए लगे थे, उसी वक्त से खर्च कर रहे हैं और अकाली एजीटेंशन में आतंकवादियों के सहारे से इस नहर की खुदाई और बंधाई बन्द कर दी है। पंजाब सरकार अपने आपको असमर्थ पा रही है। हरियाणा का पैसा फिजूल जा रहा है और हरियाणा के खेत पानी के बगैर सूख रहे हैं। मैं भारत सरकार से, जिसकी मध्यस्थता में यह फैसला हुआ था, उससे मांग करता हूं कि नीचे लिखे तरीकों से इस काम को तुरन्त समयबद्ध ढंग से करे :

1. इस नहर की खुदाई, बनाई और सरकारी इंजीनियर और कर्मचारियों की देखरेख, तनख्वाह भत्ता सब केन्द्र सरकार अपने हाथ में ले और समयबद्ध इस कार्य को करने का विश्वास हरियाणा को दिलाए।

2. या फिर पंजाब और हरियाणा का सांझा बोर्ड हो जब खर्चा हरियाणा का लगता है तो फिर उसकी देखरेख भी हरियाणा के हाथ में हो और हर दूसरे महीने काम की प्रगति की रिपोर्ट हरियाणा सरकार को दी जाए।

3. जो खर्चा अब तक लगा है, तनख्वाह और भत्तों पर, वह हरियाणा के पैसों में से न काटा जाए, उसे पंजाब सरकार वहन करे।

(iv) Need to set-up a suitable evaluating machinery to study the impact of welfare programmes on weaker sections particularly on Scheduled Castes/ Tribes.

SHRI ARJUN SETHI (Bhadrak) : The directive principles embodied in the Constitution enjoin the State to promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people particularly the scheduled castes and tribes and to protect them from social injustice and all forms of exploitation. Special efforts have been made through the successive five-year and annual plans to narrow down the existing disparities in the socio-economic conditions of scheduled castes/ tribes and the rest of the population. Various welfare programmes/schemes have been undertaken by the Government of India for meeting the special needs of these communities for the implementation of which hundreds of crores of rupees were released during the last 33 years by the Central Government to various State Governments.

But, no evaluation of the results obtained therefrom and their impact on improving the educational, economic and other interests of these communities has been made so far. I urge upon the Government to appoint a suitable evaluating machinery to study the impact of the schemes implemented and suggest measures to rectify the defects if any.

(v) Need for providing security to journalists in the country

SHRI HARIKESH BAHADUR (Gorakhpur) : Free, fair, fearless and balanced journalism is the most important element to protect the existence of democratic system